www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 09 | जौनपुर, शनिवार, 22 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

शिवसेना के विस्तार को लेकर शायना एनसी का बड़ा बयान

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने केरल में शिवसेना के विस्तार को लेकर आईएएनएस से बातचीत में प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही दावा किया कि आने वाले दिनों में केरल से हमारी पार्टी के सांसद चुने जाएंगे। केरल में शिवसेना के विस्तार पर शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, ष्हमारे जन–नेता एकनाथ शिंदे और युवाओं के प्रेरणास्रोत डॉ. श्रीकांत शिंदे ने यह सुनिश्चित किया है कि शिवसेना लगातार मजबूत हो और इसीलिए हम पूरे देश में विस्तार कर रहे हैं। हम 1996 से रक्तदान शिविरों, एम्बुलेंस सेवाओं और हर जिले में पदाधिकारियों के जरिए केरल में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज हमारे पास 13 सांसद और 60 विधायक हैं और स्थानीय निकाय चुनावों में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।ष शायना एनसी ने कहा, ष्यह गर्व की बात है कि विधानसभा में एनडीए के तीन विधायक हैं और एनडीए को शिवसेना का समर्थन हासिल है। भाजपा और शिवसेना ने विधानसभा चुनावों के लिए दिन–रात मेहनत की। मुझे लगता है कि यह तो बस एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में एक से अधिक सांसद यहां से चुने जोंगे। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर एनडीए के सांसद निर्वाचित होंगे। हमारे नेता एकनाथ शिंदे का मानना घ्है कि संस्कृति, मूल्यों या मान्यताओं से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह हिंदुत्व है, लेकिन विकास के एजेंडे के साथ। इसलिए, हम शविकसित भारतश की बात करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हर राज्य के विकसित बनने से होती है।ष वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के. सुरेंद्रन का ने कहा, ष्वी.डी. सतीशन सरकार चरमपंथी ताकतों, जमात–ए–इस्लामी, मुस्लिम लीग और कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में है। केरल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक और उससे पहले राजस्थान में (जब वहां कांग्रेस की सरकार थी) सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थीं। केरल को छोड़कर हर जगह इसे स्वीकार किया गया है।

चीनी जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई - सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी के स्टॉक की उपलब्धता की समीक्षा की और अधिकारियों को चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में अभी कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल, निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि कोई भी व्यक्ति या संस्था 30 दिनों से ज्यादा समय तक चीनी का स्टॉक जमा करके न रखे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो डीलर एक बार में 400 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ श्आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियमश और अन्य लागू नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी बताया कि राज्य में किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। कुल 3,217 करोड़ रुपये 48 लाख किसानों को बांटे गए हैं। सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई का नया सीजन 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इस बीच, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कहा कि चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी कई वजहों से हुई है, जिनमें उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों के मौसम से पहले बढ़ी हुई मांग, मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान, दुनिया भर में चीनी की सप्लाई में कमी और इंडस्ट्री के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार बाजार की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है।

नितिन नवीन ने स्मृति ईरानी समेत नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा अब देश के युवा वर्ग और खासकर जेन–जी के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने युवाओं की बदलती आकांक्षाओं, रोजगार, शिक्षा, तकनीक और स्टार्टअप जैसे मुद्दों को समझने के लिए एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम तैयार किया है। इसके लिए भाजपा ने एक उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम का गठन किया है, जिसमें संगठन के अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरे भी शामिल किए गए हैं।पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस विशेष अभियान की जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व वाली टीम को दी गई है। टीम में राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े भी शामिल हैं। इनके अलावा गुजरात सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ओपी चौधरी को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। भाजपा युवा वर्ग की प्राथमिकताओं और चिंताओं को समझने के साथ–साथ उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है।भाजपा के प्रस्तावित जेन–जी आउटरीच प्रोग्राम में रोजगार, शिक्षा, तकनीक, स्टार्टअप और नए अवसरों जैसे विषय प्रमुख रहेंगे।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2,011 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 106 इकाइयां निर्धारित पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रही थीं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के दौरान 78 इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से वैध संचालन अनुमति (सीटीओ) के बिना संचालित पाई गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निरीक्षणों के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। 44 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाया गया है, जबकि 33 नियमों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार पर्यावरण नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने या दिल्ली की वायु को प्रदूषित करने वाली इकाइयों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का अभियान केवल औद्योगिक प्रदूषण तक सीमित नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण के अन्य प्रमुख स्रोतों, जैसे सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण और विध्वंस गतिविधियां, कचरा जलाना और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

नए आपराधिक कानून पारदर्शी और तकनीक आधारित हैं – अमित शाह

कोलकाता, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पुराने औपनिवेशिक आपराधिक न्याय प्रणाली की तुलना में अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध हैं। दक्षिण–एशियाई और प्रवासी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के प्रावधानों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, ष्इन तीन नए कानूनों का उद्देश्य नागरिकों, संपत्ति और पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करना है, साथ ही आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करना भी है। इसके अलावा, ये कानून पहले की व्यवस्था की तरह केवल सजा पर केंद्रित न होकर पीड़ित–केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि जीरो एफआईआर, ई–एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्य और ऑनलाइन न्यायिक कार्यवाही जैसे प्रावधान नए कानूनों को अधिक पीड़ित–केंद्रित बनाते हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में इन तीन नए कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जानबूझकर देर से जारी की गई। उन्होंने कहा, ष्यह अधिसूचना जानबूझकर इसलिए जारी नहीं की गई क्योंकि डर था कि नए कानून लागू होते ही पिछली सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा खड़े किए गए भ्रष्टाचार के किले कुछ ही मिनटों में ढह जाएंगे। बंगाल चुनाव में हमने लोगों से डर नहीं, बल्कि विश्वास की सरकार देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, वह हमारे तीन नए न्याय संहिताओं को लागू करने और ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों को हटाने से संबंधित थी। वहीं से डर की जगह विश्वास कायम करने का काम शुरू हुआ।

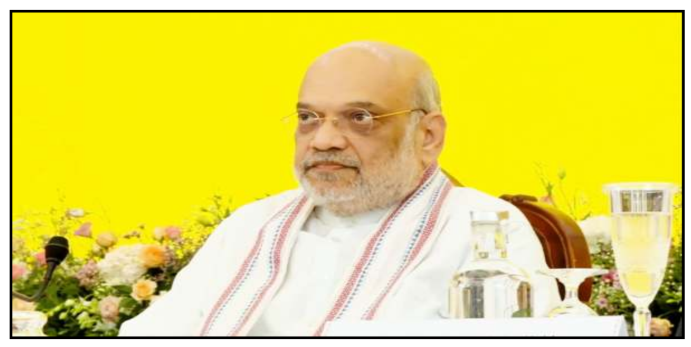

मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को 1995 की लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस घटना के बारे में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की टिप्पणियों पर बात की। उन्होंने कहा कि ने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा और हमेशा अपने सहयोगियों का साथ दिया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर अपने फायदे के लिए गठबंधन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने 1995 की उस घटना का जिक्र किया जब ठैच ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और आरोप लगाया था कि कार्यकर्ताओं ने स्टेट गेस्ट हाउस में उन पर हमला किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़तीय हम हमेशा अपने सहयोगियों के साथ खड़े रहते हैं। जो कोई भी सवाल उठाना चाहता है, उसे बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए। अभी चीनी महंगी हो गई हैय वे पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी ऊँची कीमतों पर बेच रहे हैं। यादव ने गरीबी और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने 15 करोड़ लोगों को राशन देने के सरकार के दावे पर सवाल उठाए और सरकार से लाभार्थियों की आय का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर जापान के उस बच्चे ने थोड़ी रिसर्च की होती, तो वह मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने की हिम्मत नहीं करता। उन्हें 15 करोड़ लोगों को राशन बांटना पड़ रहा हैय सरकार को इन 15 करोड़ गरीब लोगों की आय का ब्योरा देना चाहिए। वे गरीबों को कमजोर कर रहे हैंय सरकार खुद मानती है कि देश में 15 करोड़ गरीब लोग हैं। समाजवादी पार्टी अपनी सभी सीटों के लिए तैयारी कर रही है और दोगुनी रफ्तार से ऐसा कर रही है। शिक्षा और स्कूल के बुनियादी ढांचे पर बात करते हुए, यादव ने वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह प्राइमरी स्कूलों को बेहतर बनाने पर ध्यान देगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर उन स्कूलों को बंद करने का आरोप लगाया जिन्हें पहले प्राइवेट–स्टाइल के संस्थानों के तौर पर विकसित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी।

कर्नाटक में जेल विभाग के आधुनिकीकरण को कैबिनेट की मंजूरी मिली

बेंगलुरु, (एजेंसी)। कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य के जेल विभाग को आधुनिक और मजबूत बनाने की कोशिशों के तहत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले उपकरण खरीदने और लगाने को मंजूरी दे दी है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वाले कैमरे और पोर्टेबल सिग्नल जैमर शामिल हैं। गृह, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी तथा ई–गवर्नेंस मंत्री प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह फैसला मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। म्ततवत सवंकपदह के. मंत्री खड़गे ने कहा कि राज्य सरकार का मकसद राज्य की जेलों में सुरक्षा, निगरानी और कामकाज की क्षमता को बेहतर बनाना है। आधुनिकीकरण की पहल के तहत, जेलों में एआई–पावर्ड कैमरे, पोर्टेबल सिग्नल जैमर और प्रिजनर कॉलिंग सिस्टम जैसे एडवांस्ड उपकरण लगाए जाएंगे। उम्मीद है कि नई टेक्नोलॉजी से जेल परिसर के अंदर अनधिकृत गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मंत्री खड़गे ने कहा, ष्बदलती चुनौतियों को देखते हुए, जेल विभाग में भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जरूरी है। यह कदम सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करने के मकसद से उठाया गया है।ष उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी राज्य सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है, जिनके जरिए जेल विभाग के कामकाज में टेक्नोलॉजी–आधारित निगरानी और सुरक्षा उपायों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जा सके।

मुख्यमंत्री आवास योजना में 805 के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 734 पात्रों का चयन – श्वेता वर्मा

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले को मिले 805 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 737 पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है।शेष लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी है।यह जानकारी देते हुए डीडी श्वेता वर्मा ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सभी पात्र परिवारों तक पहुंचाने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान जिन पात्र लोगों को लाभ मिल चुका है।उन्हें छोडकर जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ नहीं मिल सका था।उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले ऐसे लाभार्थियों को अब इस योजना का लाभ दिया जाएगा।डीडी परियोजना ने बताया कि जिले को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुल 805 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 737 पात्र लाभार्थियों का चयन हो चुका है। शेष पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी है।

कमाई से ज्यादा खर्च, तमिलनाडु सरकार ने जुलाई में जुटाया 12,044 करोड़ का कर्ज

तमिलनाडु, (एजेंसी)। कमाई से खर्च ज्यादा होने पर तमिलनाडु सरकार की ओर से जुलाई में बॉन्ड जारी करके 12,044 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। फिस्कल डेटा के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में खर्च, कमाई से ज्यादा रहा। टीवीके सरकार की ओर से अपना पहला बजट पेश करने के 100 दिनों से ज्यादा समय बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बदलने से कामकाज के तरीके में बदलाव आएगा, लेकिन कर्ज के ताजा आंकड़ों ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर सबका ध्यान खींचा है। अप्रैल से जुलाई के बीच, तमिलनाडु को कुल 89,718 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसमें टैक्स से होने वाली कमाई का हिस्सा सबसे ज्यादा 82,566 करोड़ रुपए था, जबकि बिना टैक्स वाली कमाई 4,070 करोड़ रुपए थी। केंद्र सरकार से मिले ग्रांट से 3,082 करोड़ रुपए और आए। राज्य कई स्रोतों से कमाई करता है, जिनमें राज्य का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी), स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, जमीन से जुड़ी कमाई, बिक्री और कमर्शियल टैक्स, राज्य की एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय टैक्स में अपना हिस्सा, अन्य ड्यूटी और बिना टैक्स वाली कमाई शामिल हैं। इसे केंद्र सरकार से ग्रांट भी मिलता है। हालांकि, अप्रैल–जुलाई की अवधि में कुल खर्च 1.23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिससे 25,267 करोड़ रुपए का रेवेन्यू घाटा हुआ। मौजूदा लोन पर ब्याज का भुगतान खर्च के सबसे बड़े हिस्सों में से एक था, जो 21,176 करोड़ रुपए रहा। पेंशन भुगतान पर 17,237 करोड़ रुपए खर्च हुए। आमदनी से ज्यादा खर्च होने के कारण, सरकार कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेने पर निर्भर रही है। आम तौर पर सरकारी सिक्योरिटीज जारी करके और बैंकों व अन्य अधिकृत माध्यमों से उधार लेकर फंड जुटाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर के पहले चार महीनों में तमिलनाडु का कुल उधार 32,925 करोड़ रुपए रहा। जून तक कुल आंकड़ा 20,881 करोड़ रुपए था, जिससे पता चलता है कि राज्य ने अकेले जुलाई में अपने कर्ज में 12,044 करोड़ रुपए जोड़े। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि की तुलना में भी उधार ज्यादा था। अप्रैल और जुलाई 2025 के बीच, सरकार ने कुल 85,876 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया और 1.09 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया। उन चार महीनों के दौरान उधार 30,956 करोड़ रुपए था। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि जहां सरकार के रेवेन्यू में साल–दर–साल सुधार हुआ, वहीं खर्च और उधार भी बढ़े।

संपादकीय

नौकरी की मजबूरी

भारतीय नाविकों के सामने भी नौकरी की मजबूरी है, जिससे जहाज मालिकों का निर्देश मानने के लिए वे विवश बने हुए हैं। जबकि फारस की खाड़ी, लाल सागर, और काला सागर में जोखिम बढ़ता जा रहा है। लाल सागर में यमन के पास भारतीय झंडे वाला एक व्यावसायिक जहाज डूब गया। राहत की बात है कि जहाज पर सवार 14 नाविकों को बचा लिया गया, जिनमें 13 भारतीय हैं। भारतीय जहाज एसएसवी फैज नूर ओलिया पर यमन के हुदैदाध मोखा बंदरगाह के पास मिसाइल अथवा ड्रोन से हमला हुआ। हमला किसने किया, तुरंत यह मालूम नहीं हो सका, लेकिन यमन के पास इस जलमार्ग में जहाजों को अक्सर अंसारुल्लाह (हुती) विद्रोही निशाना बनाते रहे हैं। अंसारुल्लाह ने लाल सागर में मौजूद बाब–ए–मंदाब जल मार्ग को आम नौवहन के लिए बंद कर रखा है। इसके पहले खाड़ी में पांच महीनों से जारी युद्ध के दौरान होरमुज जलडमरूमध्य के आसपास जहाजों पर हुए हमलों में कम–से–कम 14 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। इस बीच पिछले महीने काला सागर से गुजरने का प्रयास भी भारतीय नाविकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। बीते 18 जुलाई और 19 जुलाई को दो हमलों में पांच भारतीय नाविक मारे गए। ये हमले यूक्रेन ने किए। ऐसे मामलों में भारत सरकार की प्रतिक्रिया ष्कड़ी निंदाष करने तक सीमित रही है। पिछले महीने यह खबर जरूर मीडिया में आई थी कि भारत सरकार ने शिपिंग कंपनियों को खतरनाक इलाकों में जाने वाले जहाजों में भारतीय नाविकों की ड्यूटी ना लगाने का निर्देश दिया है। ऐसे कथित निर्देश के औचित्य पर तभी कई सवाल उठे थे। बहरहाल, अब यह साफ हो चुका है कि अगर सचमुच वैसा कोई दिशा–निर्देश दिया गया था, तो वह बेअसर साबित हुआ है। तमाम नाविकों की तरह भारतीय नाविकों के सामने भी नौकरी की मजबूरी है, जिससे जहाज मालिकों का निर्देश मानने के लिए वे विवश हैं। जबकि फारस की खाड़ी, लाल सागर, और काला सागर में जोखिम बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के युद्ध में अब सबसे बड़ा मसला होरमुज का ही रह गया है, जिस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ईरान अडिग है। उधर हूतियों और सऊदी अरब के बीच लड़ाई छिडने से लाल सागर में भी खतरा बढ़ा है। इन सबके बीच भारतीय नाविकों को कैसे बचाया जाए, यह सवाल रोज अधिक बड़ा होता चला गया है।

विष्णु सरकार ने बढ़ाया किसानों का मान-खेती किसानी को मिला नया संबल

छगन लाल

प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गांव, गरीब और किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में हैं। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की इन ढाई साल के अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत् रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती–किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्यौहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदीकर न सिर्फ किसानों को मान बढ़ाया, बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। साथ ही किसानों के खाते में रमन सरकार के पिछले दो वर्ष का बकाया धान के बोनस 3716.38 करोड़ रूपए अंतरित कर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत गांवों में बसता है। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का व्यापार, उद्योग बढ़ेगा। परंपरा के अनुसार वर्षों से छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले बढ़ई के घर में गेड़ी का ऑर्डर रहता था और बच्चों की जिद पर अभिभावक जैसे–तैसे गेड़ी भी बनाया करते थे। हरेली तिहार के दिन सुबह से तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं और खेती–किसानी, औजार, हल (नांगर), कुदाली, फावड़ा, गैंती को साफ कर घर के आंगन में मुरूम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धूप–दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ के चीला का भोग लगाया जाता है। अपने–अपने घरों में अराध्य देवी–देवताओं की साथ पूजा करते हैं। गांवों के गुड़ी में ठाकुरदेव की पूजा की जाती है। हरेली पर्व के दिन पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधियुक्त आटे की लोंदी खिलाई जाती है। गांव में यादव समाज के लोग वनांचल जाकर कंदमूल लाकर हरेली के दिन किसानों को पशुओं के लिए वनौषधि उपलब्ध कराते हैं। गांव के सहाड़ादेव अथवा ठाकुरदेव के पास यादव समाज के लोग जंगल से लाई गई जड़ी–बूटी उबाल कर किसानों को देते हैं। इसके बदले किसानों द्वारा चावल, दाल आदि उपहार में यादवों को भेंट करने की परंपरा रही हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओड़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा–भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आते तक खरीफ फसल आदि की खेती–किसानी का कार्य लगभग हो जाता है। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धोकर, धूप–दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ का चीला भोग लगाया जाता है। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण किया जाता है। हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते है। गेड़ी बांस से बनाई जाती है। दो बांस में बराबर दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच से फाड़कर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। उसे नारियल रस्सी से बांधध्कर दो पउआ बनाया जाता है। यह पउआ असल में पैर दान होता है जिसे लंबाई में पहले कांटे गए दो बांसों में लगाई गई कील के ऊपर बांध दिया जाता है। गेड़ी पर चलते समय रच–रच की ध्वनि निकलती हैं, जो वातावरण को और आनंददायक बना देती है। इसलिए किसान भाई इस दिन पशुधन आदि को नहला–धुला कर पूजा करते हैं। गेहूं आटे को गूंथ कर गोल–गोल बनाकर अरंडी या खम्हार पेड़ के पत्ते में लपेटकर गोधन को औषधि खिलाते हैं। ताकि गोधन को रोगों से बचाया जा सके। गांव में पौनी–पसारी जैसे राऊत, लोहार व बैगा हर घर के दरवाजे पर नीम की डाली खोंचते हैं। गांव में लोहार अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए चौखट में कील लगाते हैं। यह परम्परा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है। पिहले के दशक में गांव में बारिश के समय कीचड़ आदि हो जाता था उस समय गेड़ी से गली का भ्रमण करने का अपना अलग ही आनंद रहता था।

क्या कैप्टन ने सरकार के कप्तान पर ही सवाल उठा दिये हैं

नीरज

पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने व्यक्ति–केंद्रित राजनीति पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा राजनीतिक सवाल दागा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पिछले एक दशक की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए कैप्टन ने अंग्रेजी समाचार–पत्र में अपने आलेख के जरिए यह संकेत दिया है कि अब भाजपा और देश की राजनीति को सिर्फ एक नाम और एक व्यक्ति के इर्द–गिर्द सिमटने की बजाय मजबूत संस्थाओं, जवाबदेही और स्थायी लोकतांत्रिक ढांचे की ओर बढ़ना चाहिए। एक तरह से कैप्टन ने भाजपा को भी सलाह दे डाली है कि मोदी–इज्म की अगली मंजिल केवल मोदी के नाम पर आगे बढ़ना नहीं, बल्कि ऐसी संस्था–केंद्रित व्यवस्था खड़ी करना होनी चाहिए, जो किसी एक नेता से परे जाकर देश की राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत को स्थायी आधार दे सके। अपने आलेख में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी के दौर ने भारतीय राजनीति और शासन की दिशा बदल दी है। उनके अनुसार, मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के एक सीमित दायरे से निकालकर देशव्यापी शक्ति में बदला। डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वित्तीय समावेशन, स्वच्छता, आवास, बिजली और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में हुए कामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने माना कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की पहुंच और डिलीवरी क्षमता का विस्तार रही है लेकिन कैप्टन का असली संदेश इससे आगे जाता है। उनका तर्क है कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता को केवल एक शक्तिशाली नेता की उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता। मजबूत सरकार और मजबूत नेता महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली मजबूती मजबूत संस्थाओं, जवाबदेही और संवैधानिक संतुलन से आती है। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी–इज्म की अगली यात्रा आखिर किस दिशा में होगी? क्या वह एक व्यक्ति के नेतृत्व के इर्द–गिर्द सीमित रहेगा या फिर ऐसी संस्थागत व्यवस्था खड़ी करेगा, जो किसी भी व्यक्ति के सत्ता से हटने के बाद भी देश को आगे बढ़ाती रहे? यहीं से कैप्टन अमरिंदर सिंह का आलेख राजनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता होते हुए भी उन्होंने संसद की भूमिका, संसदीय समितियों की जांच, संघीय विमर्श, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और नागरिक अधिकारों जैसे मुद्दों को खुलकर उठाया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र केवल नियमित चुनावों का नाम नहीं है। चुनावी जीत किसी सरकार को जनादेश जरूर देती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता के इस्तेमाल पर संस्थागत नियंत्रण कितना प्रभावी है। कैप्टन ने विशेष रूप से संसद की समितियों और संसदीय जांच की भूमिका पर जोर दिया है। उनके अनुसार, बड़े फैसलों से पहले गंभीर विचार–विमर्श और समितियों की जांच को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। संघीय ढांचे के सवाल पर भी उनका संकेत साफ है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन तथा संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता लोकतंत्र की दीर्घकालिक मजबूती के लिए जरूरी है। उनका एक और महत्वपूर्ण तर्क कल्याणकारी योजनाओं को लेकर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा, आवास, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं को किसी नेता की उदारता या राजनीतिक उपहार के रूप में नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकार और राज्य के दायित्व के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके

मुताबिक, जब शासन का आधार व्यक्ति की छवि से आगे बढ़कर संस्थागत अधिकारों और जवाबदेही पर टिकेगा, तभी विकास की प्रक्रिया स्थायी और निष्पक्ष बन सकेगी। आलेख में कैप्टन ने संविधान की मूल अवधारणाओं पर भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों पर राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को केवल राजनीतिक नारों के आधार पर नहीं आंका जा सकता। उनका तर्क है कि समाजवाद का अर्थ निजी क्षेत्र का विरोध या राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा अवसरों की समानता भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को नकारने की बजाय उन्हें भारत की नई राजनीतिक वास्तविकता का हिस्सा माना है। उनका कहना है कि पिछले एक दशक में भारत ने ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान हासिल की है। लेकिन उन्होंने यह भी चेताया है कि किसी नेता की ऐतिहासिक सफलता का अंतिम पैमाना केवल उसकी व्यक्तिगत लोकप्रियता या चुनावी जीत नहीं होती। असली कसौटी यह होती है कि उसके बाद देश की संस्थाएं कितनी मजबूत, स्वायत्त और सक्षम बनकर उभरती हैं। यानी, कैप्टन का संदेश सीधे तौर पर मोदी के नेतृत्व को खारिज करने का नहीं, बल्कि उसकी अगली मंजिल तय करने का है। उनका मानना है कि मोदी–इज्म का अगला चरण व्यक्ति–केंद्रित राजनीति से संस्था–केंद्रित राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए। मजबूत नेतृत्व अपनी जगह जरूरी है, लेकिन उसे संविधान, संसद, न्यायिक एवं संवैधानिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों की मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। देखा जाये तो पंजाब के चुनावी माहौल में एक वरिष्ठ भाजपा नेता और दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से उठाया गया यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल पंजाब की राजनीति तक सीमित नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने आलेख के जरिए राष्ट्रीय राजनीति के सामने एक बुनियादी सवाल रखा है कि क्या भारत का अगला विकास चरण केवल मजबूत नेता के भरोसे आगे बढ़ेगा, या फिर ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करेगा जो किसी भी नेता से बड़ा, ज्यादा टिकाऊ और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक जवाबदेह हो? कुल मिलाकर देखें तो कैप्टन के शब्दों का सार यही है कि भारत को मजबूत नेतृत्व चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं। और शायद यही वह बहस है, जिसे उन्होंने पंजाब चुनावों से पहले अपने आलेख के जरिए राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है।

छात्रों ने कई मुद्दों पर बुनियादी बदलाव का मैसेज दिया

राजेश पांडेय

शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से है। असंतोष और संकट के मूल में बढ़ती बेरोजगारी है। हर साल वर्क फोर्स में 70–80 लाख युवा जुड़ते हैं। 80प्रतिशत बेरोजगार 15 से 24 आयु वर्ग के हैं। ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर 29 फीसदी के आसपास है। आंदोलनों की अगली कतार में इस आयु वर्ग के लोग अधिक हैं। स्कूली छात्रों के जुड़ने का कारण अनिश्चित भविष्य तो है ही। 20 जून को जंतर–मंतर, नई दिल्ली से शुरू हुए छात्रों के आंदोलन की आवाज देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश,राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों में विद्यार्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया और रैलियां निकाली हैं। कहीं बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, स्कूलों में शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं की कमी, तो कहीं होस्टल की ज्यादा फीस जैसे मुद्दों ने छात्रों को सड़क पर आने के लिए प्रेरित किया है। बदलाव और बेचौनी की ऊर्जा से भरी यह हलचल हमारे समाज, राजनीति और सरकारी तंत्र को वर्तमान दौर की चुनौतियों को समझने और उसके हिसाब से कदम उठाने का स्पष्ट संदेश देती है।इन आंदोलनों ने कुछ अहम पहलुओं को रेखांकित किया है। कुछ नए ट्रेंड उभर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। आमतौर पर किसी मुद्दे, मांग या विषय के पक्ष–विपक्ष में जनता के विभिन्न वर्ग बड़े शहरों में एकजुट होते आए हैं। अक्सर राजनीतिक दलों, छात्रों, मजदूर संघों और सामाजिक संगठनों द्वारा जनमत जगाने, विरोध जताने और लोगों को संगठित करने की मुहिम राजधानियों या बड़े शहरों में आकार लेती है। बहुत व्यापक आंदोलनों को छोड़ दें तो कई बार वह उन्हीं स्थानों तक सिमटकर रह जाती है। इस बार स्थिति अलग है। दिल्ली, भोपाल, रायपुर जैसी राजधानियों से उठी आवाज की अनुगूंज छोटे शहरों में सुनाई पड़ रही है।एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले लोगों के स्वरूप में हुआ है। कॉलेज छात्रों के साथ स्कूली छात्र आगे आए हैं। स्कूली छात्र सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित नहीं हैं। कई जगह मिडिल स्कूल के छात्रों ने सीनियर साथियों के साथ मोर्चा संभाला है। लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। वे सिर्फ दिल्ली या राजधानियों में ही नहीं छोटे शहरों तक में सड़क पर उतरी हैं। सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर है, वे मौजूदा स्थितियों में अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें जिंदगी की दौड़ में पिछड़ने का खतरा नजर आता होगा।छोटे शहरों के छात्रों के जागरूक होने का मुख्य कारण उनकी मांग तो है ही पर सोशल मीडिया ने उनके लिए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। मोबाइल के परदे का छोटा स्क्रीन उन्हें दिल्ली से लेकर सैनफ्रांसिस्को तक की हलचल की जानकारी देता है। वे सिर्फ रील बनाने, देखने या मनोरंजन तक सीमित नहीं होंगे। उन्हें साइंस, टेक्नालॉजी, इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों की खबरें मिल रही हैं। स्पेस साइंस के चमत्कार भी उनकी कल्पनाओं का हिस्सा बन रहे होंगे। वे देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका के कोई मार्क जकरबर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप जैसा टूल बनाते हैं तो कैसे ओपन एआई के सैम आल्टमैन चौट जीपीटी पेश कर रहे हैं। वे यह भी जानने लगे हैं किस तरह मेडिकल साइंस ने दिल और मस्तिष्क के रोगों सहित कई लाइलाज बीमारियों में राहत देने का रास्ता खोज लिया है।सूचना क्रांति का वर्तमान समय छात्रों सहित हर किसी को लोकतंत्र, आजादी और खुलेपन की अहमियत बताता है। वह उनके अंदर सिस्टम की जड़ता को तोड़ने और नई राह पर चलने की बेचौनी पैदा करता है। उन्हें कहीं लगता है कि वे असली बदलाव से बहुत दूर हैं। युवा महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था उन्हें सिर्फ प्रतियोगिता की अंतहीन होड़ में झोंक रही है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को नैतिकता, ईमानदारी, विश्वसनीयता और मानवीय मूल्यों के प्रसार का वाहक होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। हम हर कहीं मूल्यों का क्षरण देखते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा अपने पुराने ढर्रे पर चल रहा है।ऐसे सिस्टम से युवाओं का मोहभंग और हताशा स्वाभाविक है। आधुनिक दौर में ऐसी व्यवस्था के खिलाफ ताकतवर स्वर उभरते रहे हैं। युवाओं और आम लोगों ने समय–समय पर सत्ता को झकझोरने के लिए अपना असंतोष जाहिर किया है। छात्रों के सत्याग्रह का जिक्र होता है तो मार्च, मई 1968 में फ्रांस के छात्र आंदोलन को हमेशा याद किया जाता है। उस वक्त पेरिस में छात्रों ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में छात्रों की भीड़, शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त साधनों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। देश की ट्रेड यूनियन भी छात्रों के साथ खड़ी हो गई थीं। आंदोलन दूसरे शहरों में फैल गया। मजदूर संघों के साथ आने से कारखानों, दफ्तरों में काम ठप पड़ गया था। फ्रांस के आंदोलन में तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डिगाल की दस साल लंबी सत्ता का विरोध भी जुड़ा था। डिगाल का शासन अनुदारवादी था। उनकी तानाशाही और मनमानी के खिलाफ नौजवानों और मजदूर वर्ग में असंतोष पनप रहा था। डिगाल ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने नेशनल असेम्बली भंग कर दी। नए चुनाव कराए। देश में फैली अस्थिरता से परेशान मध्यम वर्ग ने डिगाल का समर्थन किया। उनकी पार्टी को संसद में फिर बहुमत मिल गया। 1969 में डिगाल ने संसद के स्वरूप में बदलाव के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया। लेकिन जनमतसंग्रह में हारने पर अप्रैल में उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। भारत में विभिन्न स्तरों पर चल रही छात्रों की हलचल का संबंध व्यवस्था विरोधी भी है। निश्चित रूप से वह स्कूल, कॉलेजों में साधनों के अभाव से जुड़ा है। शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.8 से 4.3 प्रतिशत के बीच चल रहा है। वैसे, राष्ट्रीय नीति में शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की नीति रही है। लेकिन सरकारें इसका पालन नहीं कर रही हैं। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा राज्यों का विषय है। इसलिए राज्यों के हिस्से में शिक्षा के खर्च का हिस्सा 75 प्रतिशत और केंद्र सरकार का 25 प्रतिशत है। प्रचार अभियान और चुनाव शिक्षा की पहली सीढ़ी स्कूल हैं। इसलिए उसके खर्च में कमी का असर भविष्य में शिक्षा के प्रसार और उसके स्तर पर पड़ता है। अपर्याप्त बजट का नतीजा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, शाला भवनों की दुर्दशा और अन्य सुविधाओं के अभाव में सामने आया है। विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के स्कूल ज्यादा अभावग्रस्त हैं। शिक्षा के प्रति सरकारों की उपेक्षा को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कर सकते हैं। देश में 2014–15 से 2024–25 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 94 हजार कम हुई है। इसमें उन स्कूलों की संख्या शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकारें किसी अन्य स्कूल में शामिल करती हैं।

प्राकतिक खेती – सतत कृषि और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

डॉ. देवेश चतुर्वेदी

भारत ने पिछले दशक में कृषि क्षेत्र में तेज प्रगति की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, पिछले 5 सालों में विकास दर 4त्न से अधिक रही है। खाद्यान्न, बागवानी और तेलहन फसलों का बंपर उत्पादन हुआ है। यह किसानों द्वारा नई तकनीकों को अपनाने और सिंचाई वाले क्षेत्र का विस्तार, बेहतर जल उपयोग दक्षता और समय पर व पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्धता जैसी सरकार की ठोस नीतियों के समर्थन का परिणाम है। बागवानी फसलों की हिस्सेदारी भी काफी बढ़ रही है और इसकी विकास दर अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और प्रमुख फसलों की उत्पादकता में स्थिरता आ रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (एनयूई) में धीरे–धीरे आई कमी के कारण एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है, जिसमें किसान रासायनिक खादों की मात्रा तो लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादकता में बहुत मामूली बढ़ोतरी ही हो रही है। सरकार की मृदा स्वाथ्य और उर्वरक योजना के तहत 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण किया गया है। इससे प्राप्त डेटा के अखिल–इंडिया विश्लेषण से चिंताजनक बात सामने आई है कि मिट्टी में जैविक कार्बन (एसओसी) और अन्य जरूरी सूक्ष्म–पोषक तत्वों की भारी कमी है। स्वस्थ मिट्टी में एसओसी 1त्न से अधिक होना चाहिए, लेकिन यह औसतन 0.5त्न के आसपास है और कुछ क्षेत्रों में यह 0.3त्न तक के यह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कम मात्रा में एसओसी से मिट्टी की सरंध्रता कम हो जाती है, जिसका दोहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैरू पानी का जमीन में रिसाव और जल धारण क्षमता, दोनों में कमी आती है। परिणामस्वरूप, वर्षा और सिंचाई का पानी बह जाता है, जो ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है और न तो यह जमीन के नीचे जाकर भूजल स्तर बढ़ा पाता है और न ही पौधों की वृद्धि के लिए आसानी से उपलब्ध रहता है। कम एसओसी का एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि ऐसे मिट्टी पर उगाए जाने वाले पौधों की पोषक तत्व अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। समान उत्पादकता स्तर तक पहुँचने के लिए अधिक से अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई खुराक उर्वरक उपयोग दक्षता को और कम कर देती है, जिससे मृदा–स्वास्थ्य का नुकसान होता है और देश रासायनिक उर्वरकों या उनके घरेलू उत्पादन के कच्चे माल को आयात करने में अपनी कीमती विदेशी मुद्रा खर्च करता है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के असंतुलित उपयोग ने उन लाभकारी सूक्ष्मजीवों और कीड़ों को भी कम कर दिया है, जो मिट्टी की सरंध्रता को बेहतर बनाने और गहरी मिट्टी से पोषक तत्वों को ऊपरी मिट्टी तक स्थानांतरित करने में मदद करते हैं, ताकि पौधे उन्हें अवशोषित कर सकें। एक अन्य चिंताजनक प्रभाव उपज की गुणवत्ता और सुरक्षा पर पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि रसायन खाने–पीने और पशु चारे की श्रृंखला में पहुँच जायेंगे और आखिरकार मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करेंगे। ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें फलों, सब्जियों, अनाज और अन्य वाणिज्यिक फसलों में कीटनाशकों का न्यूनतम अवशेष स्तर तय सीमा को पार कर गया है, जिसके चलते निर्यात की खेपें रद्द होती हैं और वैश्विक बाजार में ब्रांड इंडिया की छवि पर बुरा पड़ता है। हालांकि ये चिंताएँ कुछ समय से व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन सरकार ने वर्ष 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत कृषि के लिए पशुधन या गाय आधारित रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है, ताकि मिट्टी की सेहत खासकर एसओसी में सुधार हो सके, पौष्टिक तत्वों के अवशोषण की क्षमता बढ़ सके और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर देश की निर्भरता कम हो सके। प्राकृतिक खेती, जिसे इसके समर्थकों द्वारा आमतौर पर श्जीरो बजट खेतीश कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक पर आधारित है, जिसे किसानों ने कई सालों तक आजमाया और परखा है तथा इसे मान्यता दी है। इसके परिणाम भी बहुत उत्साहजनक रहे हैं। यह एक समग्र तकनीकी समाधान पर आधारित है, जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे स्थानीय नस्ल की गाय का गोबर और गोमूत्र, जिनकी लागत किसान के लिए लगभग शून्य होती है। बीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाला बीजामृत सूत्र बेहतर अंकुरण और मजबूत पौधों में मदद करता है, जबकि जीवामृत, घन–जीवामृत और सप्तयांकुर का उपचार मित्र सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी और मृदा–उत्पादकता को काफी बढ़ा देता है। पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा सौंठास्त्र और खट्टी लस्सी के इस्तेमाल से की जाती है, जो बैक्टीरिया और फफूंद संक्रमण को रोकते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के कीड़ों और कीट को नियंत्रित करने के लिए श्नीमास्त्रश, श्ब्रह्मास्त्रश, श्अग्निअस्त्रश और श्दशपर्णी अर्कश का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी उपचारों की सावधानीपूर्वक तैयारी और उचित मात्रा में उपयोग से मिट्टी की सेहत के बेहतर परिणाम मिले हैं और उत्पादकता पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि उपज की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मिशन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से प्रगति कर रहा है, जिसका लक्षित क्षेत्र 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक है और यह 18 लाख से अधिक किसानों को कम से कम 50 हेक्टेयर के क्लस्टर में कवर करता है। कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की टीम, जिसे किसान प्रशिक्षक और कृषि सखी संसाधन व्यक्ति के रूप में सहायता प्रदान कर रहे हैं, किसानो को जागरूक कर रही है, प्रशिक्षण दे रही है और इस खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जिन किसानों के पास स्थानीय नस्ल की गायें हैं, उन्हें खेत पर ही इन उपचारों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, बड़ी संख्या में जैव–इनपुट संसाधन केंद्र भी मुख्य रूप से स्थानीय डेयरियों या पशु आश्रय गृहों के निकट स्थापित किए गए हैं, ताकि ये उपचार किसानों को मामूली कीमत पर उपलब्ध कराए जा सकें। यह मिशन विज्ञान–आधारित रणनीति के माध्यम से लागू किया जा रहा है, ताकि किसान इन प्रथाओं को बिना किसी संदेह या हिचकिचाहट के अपना सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने क्षेत्र और फसल–विशिष्ट क्षमता मानचित्र विकसित किए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्राकृतिक खेती कहाँ प्रभावी होगी। आईसीएआर के संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में इस देसी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए इसकी प्रभावशीलता को वैज्ञानिक रूप से मान्यता देने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। आईसीएआर संस्थानों की निगरानी में किए गए कई प्रयोगों ने कई फसलों के लिए बहुत सकारात्मक परिणाम दिए हैं और अब मिशन के जरिए इनका प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। प्राकृतिक उत्पादों का विपणन एक और महत्वपूर्ण रणनीति है, जो किसानों की आय में वृद्धि करेगी और उन्हें इन प्रथाओं को जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी। राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र (एनसीओएनएफ) ने प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणीकरण नियम बनाये हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने पहले ही सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं, जिससे वे अपने प्रमाणित विशिष्ट उत्पाद को ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं।

संक्षिप्त खबरें

डीसीएम की टक्कर से कांवड़िये की मौत, साथी घायल

लखनऊ, (संवाददाता)। इटौंजा थाना क्षेत्र में सीतापुर–लखनऊ हाईवे पर गुरुवार को अज्ञात डीसीएम की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक कांवड़िये की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और अज्ञात डीसीएम की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त को करीब 3:30 बजे मोटरसाइकिल संख्या यूपी32 डीए 5383 पर सवार सत्यम गुप्ता (17) पुत्र राकेश गुप्ता, निवासी कुर्सी हिरोरा, थाना संदना, सीतापुर और शोभित गुप्ता (18) पुत्र आशीष कुमार, निवासी पलटूपुर, थाना घूंघटेर, बाराबंकी, सीतापुर से लखनऊ की ओर जा रहे थे।इटौंजा थाना क्षेत्र में सीतापुर–लखनऊ हाईवे पर लाडली होटल के सामने एक अज्ञात डीसीएम वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए रामसागर मिश्र 100 शैय्या अस्पताल, साढ़ामऊ, बीकेटी पहुंचाया।अस्पताल में चिकित्सकों ने सत्यम गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। वहीं शोभित गुप्ता को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ रेफर कर दिया गया। इटौंजा पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू, लखनऊ भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हादसे में शामिल अज्ञात डीसीएम वाहन की तलाश कर रही है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के मुताबिक, वर्तमान में यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है और घटनास्थल पर कानून–व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है।

मारपीट में राजमिस्त्री की मौत, दो आरोपी हिरासत में

लखनऊ, (संवाददाता)। सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के अमौसी में मकान बनाने के औजार और अन्य सामान गायब होने के विवाद में हुई मारपीट के बाद एक राजमिस्त्री की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, मृतक आशीष कुमार द्विवेदी (30) मूल रूप से ग्राम टेमौं, थाना रामसनेहीघाट, बाराबंकी का रहने वाला था और वर्तमान में अमौसी में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। 19 अगस्त को करीब तीन बजे मकान बनाने के औजार और कुछ अन्य सामान गायब होने की बात को लेकर उसका फूलचंद्र श्रीवास्तव (42) और कल्लू उर्फ श्यामलाल रावत (47) से विवाद हो गया।विवाद के दौरान हुई मारपीट में आशीष को चोटें आईं। उसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर में कराया गया था। 20 अगस्त की सुबह करीब नौ बजे आशीष की उसके घर पर मौत हो गई।सूचना मिलने पर सरोजनीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू की। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सरोजनीनगर में मु0अ0सं0 320⁄2026, धारा 105, 115(2) और 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बिजनौर पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर थाना पुलिस ने अवैध तमंचा लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।पुलिस के अनुसार, उपनिरीक्षक आनंद प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ बिजनौर चौराहे से कस्बा बिजनौर की ओर पैदल गश्त कर रहे थे। बिजनौर बाजार के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गोलू होटल के सामने से नक्श सिटी जाने वाले मार्ग पर एक युवक तमंचा लेकर घूम रहा है।सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर रास्ते पर तमंचा लेकर घूम रहे युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।गिरफ्तार आरोपी की पहचान हुमेद उर्फ हुमैर (26) पुत्र स्वर्गीय सगीर, निवासी घसियारी मोहल्ला, कस्बा व थाना बिजनौर, लखनऊ के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना बिजनौर में मु0अ0सं0 223⁄2026, धारा 3⁄25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को 20 अगस्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले उसे यह तमंचा जंगल में पड़ा मिला था। इसके बाद उसने तमंचे को अपने पास रख लिया और कभी–कभी शौकिया तौर पर इसे लेकर घूमता था ताकि लोग उससे डरते रहें। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है।

पीढ़ितों और बच्चों से संवेदनशील संवाद के लिए 68 रिक्रूट आरक्षियों को दिया गया प्रशिक्षण

लखनऊ, (संवाददाता)। समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और समावेशी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट लखनऊ में वर्ष 2025 बैच के रिक्रूट आरक्षियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। 20 अगस्त को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में आयोजित कार्यशाला का विषय "पीड़ितों एवं बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व संवेदनशील संवाद कैसे स्थापित किया जाए" रहा।उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमिश्नरेट लखनऊ के सभी थानों से वर्ष 2025 बैच के 68 रिक्रूट आरक्षियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य नवआरक्षियों को संवेदनशील, सजग और प्रभावी प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले पुलिसकर्मी के रूप में तैयार करना रहा।प्रशिक्षण सत्र में यूनिसेफ की डिविजनल कंसल्टेंट रिजवाना परवीन ने प्रतिभागियों को पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने के व्यवहारिक तरीकों की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि घटनास्थल अथवा थाने पर पहुंचने के बाद पीड़ित की बात धैर्यपूर्वक सुनना, उसकी भावनात्मक स्थिति को समझना और उसे आवश्यक सहयोग एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।कार्यशाला में संवाद कौशल और व्यवहारिक विकास के साथ महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े विभिन्न कानूनों और प्रावधानों की जानकारी दी गई।

छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, पैलेट गन चलाने वालों पर नामजद FIR की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में दिल्ली के जंतर–मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार शाम जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में धरना–प्रदर्शन शाम 7रू30 बजे से 8 बजे तक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन चलाने और लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। डॉ. प्रमोद सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार पुलिस और लाठी–डंडों के बल पर छात्रों एवं नौजवानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी छात्रों एवं युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने भी पैलेट गन चलाने वालों और इसके आदेश देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह डब्बू, अरुण शुक्ला, इरशाद खान राजू, फैयाज हाशमी, सभासद शहनवाज मंजूर, राजकुमार गुप्ता, जयप्रकाश मिश्रा, इकबाल हुसैन, मुहम्मद ताहिर, संदीप निषाद, गौरव कुशवाहा, रोहित सोनकर, कार्तिक मौर्या सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विकास कार्यो को प्राथमिकता दे रही योगी सरकार - गिरीश चंद्र यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में अवस्थापना निधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत विकास कार्य का शनिवार को शिलान्यास किया गया। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव ने विकास भवन से जिला पंचायत कार्यालय तक 250 मीटर इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस विकास कार्य पर 53.12 लाख रुपये की लागत आएगी। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में आवागमन सुगम होने के साथ ही जल निकासी की व्यवस्था भी बेहतर होगी। शिलान्यास के दौरान राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शहरों और सरकारी परिसरों में बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि जौनपुर में भी सड़क, नाली, जल निकासी सहित आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में होने वाला यह कार्य कर्मचारियों, अधिकारियों और यहां आने वाले आम लोगों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराकर आम जनता को उसका सीधा लाभ पहुंचाना है। कलेक्ट्रेट परिसर में इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण से जलभराव की समस्या कम होने के साथ परिसर की व्यवस्था भी बेहतर होगी।

डेयरी क्षेत्र में 6937 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 11 हजार नए रोजगार की उम्मीद

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में उन्नत नस्ल के गोवंश को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में डेयरी क्षेत्र की भूमिका मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में दुग्ध विकास विभाग की ओर से 'नंद बाबा दुग्ध मिशन' और दुग्ध प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रचार–प्रसार तथा डेयरी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित मंडलवार 'डेयरी कॉन्क्लेव–स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद' श्रृंखला के तहत बरेली में कार्यशाला आयोजित की गई।भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली में आयोजित कार्यक्रम में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समृद्ध संभावनाओं वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये मंडल प्रदेश के डेयरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभा सकते हैं।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल दूध उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि दूध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, कोल्ड चेन और डेयरी उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और निवेश की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।अपर मुख्य सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश कुमार मेश्राम ने देशी नस्ल के गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के बहुआयामी लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभाव सीधे पशुपालकों और गोपालकों के जीवन स्तर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने उन्नत देशी गोवंश, समृद्ध निवेश, सुरक्षित भविष्य और खुशहाल उत्तर प्रदेश के संकल्प को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। किसानों को सुनिश्चित बाजार, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और स्थायी आय उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन और दुग्ध नीति–2022 के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन, आधुनिक डेयरी विकास और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

फिर धंसा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, एक साथ 700 मीटर तक आई लंबी दरारें, एक लेन करनी पड़ी बंद

लखनऊ, (संवाददाता)। कानपुर–लखनऊ एक्सप्रेसवे की जहां 16 दिन पहले 200 मीटर सड़क धंसी थी, उसी के पास 700 मीटर सड़क में

कई जगह दरारें और नाली (व्हील) ट्रैक बन गई है। बुधवार की रात 100 मीटर धंसी सड़क का पैचवर्क करने के बाद बृहस्पतिवार सुबह से 600 मीटर सड़क ठीक करने का काम कराया गया। निर्माण एजेंसी पीएनसी सड़क की ऊपरी परत को हटाकर नई परत बिछा रही है। एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने का सिलसिला लोकार्पण के 12वें दिन 25 जुलाई को शुरू हो गया था। सबसे पहले किलोमीटर संख्या 64.4 पर कोरारी और अड़ेरुआ गांव के बीच सड़क धंसी थी। पीएनसी ने आनन–फानन खामियों पर पर्दा डालते हुए पैचवर्क करा दिया था लेकिन 11वें ही दिन पांच अगस्त की रात इसी स्थान पर सड़क 200 मीटर दायरे में धंस गई और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गुणवत्ता से खिलवाड़ सामने आ गया था। लगातार एक सप्ताह तक मरम्मत का काम चला और इस दौरान एक्सप्रेसवे की बदहाली सुर्खियों में आ गई थी। बुधवार रात किलोमीटर संख्या 61.4 से 63 किमी तक फिर दरार आ गई और और करीब तीन मीटर में व्हील ट्रैक बन गए। निर्माण एजेंसी पीएनसी ने रात में ही मरम्मत का काम शुरू किया और किलोमीटर संख्या 62 से 62.1 तक सौ मीटर सड़क बनाई और बृहस्पतिवार सुबह कानपुर से लखनऊ जाने वाली सड़क की दो लेन को बंद करके किमी संख्या 61.4 से 62 तक मरम्मत शुरू कराई।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा ने निकाला तिरंगा यात्रा, पेंशन के नारे से गूंज उठा कलेक्ट्रेट जौनपुर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर अटेवा के आह्वान पर जौनपुर में विशाल 'तिरंगा यात्रा' एवं 'पेंशन बचाओ रैली' का आयोजन किया गया। अटेवा के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विकासखंडों से बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हुए और पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में अपनी एकजुटता का जोरदार प्रदर्शन किया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ अंबेडकर तिराहा से हुआ। हाथों में तिरंगा और पुरानी पेंशन बहाली के नारों के साथ शिक्षक–कर्मचारियों का काफिला कलेक्ट्रेट जौनपुर पहुंचा। यहां पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित कर्मचारियों के हितों से जुड़ी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के उपरांत तिरंगा यात्रा का शांतिपूर्ण एवं सफल समापन हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व अटेवा जिलाध्यक्ष चंदन सिंह, जिला महामंत्री इंदुप्रकाश यादव एवं जिला कोषाध्यक्ष नंदलाल पुष्पक ने किया। वहीं कार्यक्रम प्रभारी एवं प्रमुख वक्ता के रूप में अटेवा मंडल उपाध्यक्ष रमेश यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिरंगा यात्रा में विभिन्न शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की गरिमामयी सहभागिता रही। कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुजीत सिंह, सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय चौधरी, बिजली विभाग के निखिलेश सिंह, बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह, विकास सिंह, संजय सिंह,निखिलेश सिंह , हेमंत सिंह तथा पूर्वांचल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के नंद किशोर सिंह सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने यात्रा में सहभागिता कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को अपना समर्थन दिया। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की इस व्यापक सहभागिता ने स्पष्ट संदेश दिया कि पुरानी पेंशन की मांग किसी एक संगठन अथवा वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग के सुरक्षित भविष्य, सम्मानजनक सेवानिवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा साझा संघर्ष है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वर्षों तक पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ सरकारी सेवा करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। अटेवा महिला विंग की प्रदेश सह प्रभारी डा यामिनी सिंह एवं महिला विंग जौनपुर की अध्यक्ष आराधना चौहान ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए कोई भीख या खैरात नहीं, बल्कि वर्षों की सेवा के बाद सम्मानजनक और सुरक्षित बुढ़ापे का अधिकार है। पूनम जयसवाल एवं विनीता यादव ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, तब तक अटेवा का संघर्ष पूरी मजबूती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद तिरंगा यात्रा में शिक्षक–कर्मचारियों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। हाथों में तिरंगा लिए प्रतिभागियों ने "पुरानी पेंशन बहाल करो", "जय युवादृजय अटेवा" और "विजय बंधु जिंदाबाद" जैसे नारों से पूरा जिला मुख्यालय गुंजायमान कर दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षक–कर्मचारियों ने अनुशासन, एकजुटता और संघर्ष के संकल्प का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

आरटीओ कार्यालय में कथित धनउगाही के आरोप, जांच के लिए पहुंचे उप परिवहन आयुक्त

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में आरटीओ कार्यालय में वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कथित धनउगाही का मामला सामने आने के बाद शनिवार को उप परिवहन आयुक्त भीमसेन सिंह और एआरटीओ प्रशासन राघवेंद्र सिंह ने कार्यालय पहुंचकर जांच की। अधिकारियों के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उससे निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त रकम की मांग की गई। मड़ियाहूं निवासी ट्रक मालिक विनय कुमार सिंह के मुताबिक, उन्होंने करीब तीन करोड़ रुपये की पांच ट्रेलर गाड़ियां खरीदी हैं। इनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनकी गाड़ियां चार दिनों से आरटीओ कार्यालय में खड़ी थीं। शुक्रवार को उन्होंने कार्यालय के गेट पर पांचों गाड़ियां खड़ी कर करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन किया। विनय सिंह का आरोप है कि कार्यालय में तैनात बाबू गणेश मिश्रा ने प्रत्येक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार रुपये, यानी कुल 50 हजार रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि आरआई ने गाड़ियों की माप कर उन्हें ‘ओके’ कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई। उनका कहना है कि वाहनों के खड़े रहने से उन्हें किश्तों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसी समस्याओं के कारण जौनपुर की कई गाड़ियां बिहार में पंजीकृत कराई जा रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। आरआई अशोक यादव ने बताया कि संबंधित बाबू गणेश मिश्रा हाईकोर्ट गए हुए हैं। उनके स्थान पर दूसरे बाबू को नामित कर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद गाड़ियों को भी हटवा दिया गया है। शनिवार को जांच के लिए पहुंचे उप परिवहन आयुक्त भीमसेन सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबू गणेश दत्त को रजिस्ट्रेशन पटल से हटाकर डिस्पैच पटल का काम सौंपा गया है। इस संबंध में लिखापढ़ी कर शासन को भेजी जा रही है। वहीं, शिकायतकर्ता विनय सिंह ने कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि यदि ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह मंगलवार तक धरने पर बैठेंगे। उन्होंने दावा किया कि जिले के कई मोटर मालिक ऐसी समस्याओं से परेशान हैं।

चंपत राय के पत्र पर नृपेंद्र मिश्रा बोले– मैंने पत्र नहीं देखा, राम मंदिर निर्माण को लेकर दी जानकारी

लखनऊ, (संवाददाता)। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना करोड़ों श्रद्धालुओं के सपने के साकार होने जैसा है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर निर्माण में केंद्र या राज्य सरकार का पैसा नहीं लगा है। मंदिर और परिसर के निर्माण का कार्य ट्रस्ट द्वारा एकत्रित धनराशि से कराया गया है। निर्माण के लिए तय किए गए करीब 70 कार्यों में से लगभग 60 कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिन निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है, उन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है। अब इन निर्माणों के रखरखाव की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। मंदिर परिसर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था को मुख्य नाले से जोड़ने की योजना पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी की निकासी को बेहतर बनाना है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अब रामकथा संग्रहालय, ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संग्रहालय की गैलरी नंबर–7 के निर्माण पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। संग्रहालय में प्रवेश शुल्क लिया जाएगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय ट्रस्ट करेगा। चंपत राय के पत्र में अपना नाम होने को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उन्होंने वह पत्र देखा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट किया कि वह इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

छात्रवृत्ति से वंचित 3.16 लाख विद्यार्थियों को एक और मौका, 1 सितंबर से फिर खुलेगा पोर्टल

लखनऊ, (संवाददाता)। वित्तीय वर्ष 2025–26 में तकनीकी कारणों से दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए पात्र छात्र–छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और अवसर देने का फैसला किया है। बड़ी पहल करते हुए समाज कल्याण विभाग 1 सितंबर 2026 से छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलेगा, ताकि तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित रह गए पात्र विद्यार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जा सके। इस व्यवस्था का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा।सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 3 लाख 16 हजार 57 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में तकनीकी कारणों से इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सका था।

'जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने राजकीय इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों से किया संवाद'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' शनिवार को जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने राजकीय इण्टर कॉलेज पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से उनकी पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हुए उनकी जिज्ञासाओं और समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा आवश्यक मार्गदर्शन दिया। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाई करने, समय का सदुपयोग करने तथा अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा के साथ–साथ अनुशासन, संस्कार और जिम्मेदारी की भावना को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिलाधिकारी ने छात्रों से कहा कि यदि कोई समस्या हो तो सर्वप्रथम सम्बन्धित अधिकारी के संज्ञान मे लाते हुये उसका निस्तारण कराये। उन्होंने छात्रों को गुड सेमेरिटन योजना के विषय में बताते हुये कहा कि योजना के अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों की मदद करने वाले नागरिकों को रू 25000 की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने राजस्व व्यवस्था की प्रणाली, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आदि के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी छात्र अत्यन्त प्रतिभावान है, इसलिये सभी को पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करते हुये अपने जनपद का नाम रोशन करने हेतु प्रयास करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें साइबर अपराध से बचाव, यातायात नियमों का पालन करने तथा सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बिना संकोच अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा पुलिस को इसकी जानकारी दें। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस व्यवस्था के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी को अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान छात्रों ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से विभिन्न विषयों पर सवाल किए। अधिकारियों ने विद्यार्थियों के सवालों का सरलता से जवाब देते हुए उन्हें बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। संवाद के दौरान विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान पढाई में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के अन्त में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ अरविन्द कुमार पाठक ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्राचार्य डायट रामेन्द्र कुमार, प्राचार्य जीआईसी श्याम नारायण यादव, जिला सेवायोजन अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज में छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में शनिवार को राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल द्वारा छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को जीवन लक्ष्य निर्धारण, कैरियर नियोजन तथा उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। संवाद के दौरान छात्राओं के साथ प्रभावी अध्ययन पद्धति, समय प्रबंधन, आत्म–अनुशासन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्र हितकारी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान कक्षा–12 की छात्राओं साक्षी दीक्षित, अदिति आर्या एवं निशी द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। छात्राओं ने तैयारी के दौरान होने वाली व्याकुलता से बचने, सीमित संसाधनों एवं विषय विशेषज्ञ मार्गदर्शन की व्यावहारिक सीमाओं के बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वयं को तैयार करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में अपनी जिज्ञासाएं एवं समस्याएं रखीं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग, अनुशासन, उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग तथा आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया। छात्राओं को बताया गया कि सीमित संसाधन सफलता में बाधा नहीं हैं, बल्कि सही रणनीति, निरंतर मेहनत एवं दृढ़ इच्छाशक्ति के माध्यम से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, हरदोई स्वाति श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ प्रवक्ता सुमन द्विवेदी सहित विद्यालय के शिक्षकगण उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार द्वारा छात्राओं के लिए आयोजित इस संवाद कार्यक्रम को उपयोगी एवं प्रेरणादायी बताया गया।

संक्षिप्त खबरें

मोक्षधाम तक पहुंचने में विकास की अग्निपरीक्षा, कीचड़ में फंसी व्यवस्था

भदोही, (संवाददाता)। कालीन नगरी में विकास के दावे कागजों में दौड़ते हैं, लेकिन मोक्षधाम तक जाने वाली सड़कों पर कीचड़ है। मोक्षधाम तक पहुंचने के लिए अग्निपरीक्षा देनी पड़ती है। हालत यह है कि अंतिम सफर पर निकले व्यक्ति को भी मुक्ति आसानी से नहीं मिल पा रही। परिजनों को अर्थी कीचड़ से होकर ले जानी पड़ रही है। ग्राम पंचायतों की उदासीनता से गंगा किनारे बने अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। जिले में 45 किलोमीटर परिक्षेत्र में गंगा का दायरा है। साल 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने की मुहिम शुरू की गई। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के किनारे शवदाह रोकने के लिए उससे सटे ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह यानी अंत्येष्टि स्थल बनाने की योजना शुरू हुई। 2015–16 में गोपालापुर कलिंजरा, सेमराध, सीतामढ़ी, बरजी, बदरी, बिहरोजपुर, बेरासपुर, मवैया थान सिंह, दुगुना, खेमापुर सहित 21 ग्राम पंचायतों में इसका निर्माण शुरू हुआ। प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल के निर्माण पर 15 लाख रुपये खर्च हुए। साल 2022–23 में तीन अन्य अंत्येष्टि स्थल 24–24 लाख से बनाए गए। बृहस्पतिवार को हमारी टीम ने सीतामढ़ी, बिहरोजपुर, कौलापुर, बेरासपुर, बरजी और बदरी के अंत्येष्टि स्थलों की पड़ताल की तो स्थिति काफी खराब मिली। निर्माण के समय प्रधान, सचिव और अन्य विभागीय अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। यहां बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बारिश में कीचड़ और गंदगी भरी सड़कें लोगों की समस्या और भी बढ़ा रहीं हैं। जिससे शव लेकर आने वाले लोग मुक्तिधाम पर रुकने की बजाय गंगा के किनारे ही शवदाह कर रहे हैं।

वित्तपोषित माध्यमिक स्कूलों को जल्द मिलेंगे 42 शिक्षक

भदोही, (संवाददाता)। जिले के 25 वित्तपोषित विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर होगी। आयोग की ओर से सात प्रवक्ताओं का चयन कर भेज दिया गया, जबकि 35 एलटी ग्रेड के शिक्षक माह के अंत तक आएंगे। इससे शिक्षकों की कमी के कारण पठन–पाठन प्रभावित नहीं होगा। टीजीटी–पीजीटी 2022 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन कर भेजा जा रहा है। जिले में 38 राजकीय, 25 वित्तपोषित और 150 से अधिक वित्तविहीन विद्यालय संचालित हैं। राजकीय और वित्तपोषित विद्यालयों में लंबे समय से कई विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। विद्यालय प्रबंधतंत्र प्राइवेट शिक्षकों के सहारे पठन–पाठन बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। अब आयोग की ओर से शिक्षकों का आवंटन किए जाने से विद्यालयों को राहत मिलने की उम्मीद है। वित्तपोषित विद्यालयों की ओर से भेजे गए अधियाचन के आधार पर आयोग ने शिक्षकों का चयन कर भेजना शुरू किया है। शिक्षकों की तैनाती होने से विद्यालयों में पढ़ाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। विभागीय स्तर पर शिक्षकों के जिले में पहुंचने और विद्यालयों में तैनाती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित विषयों की पढ़ाई सुचारू हो सकेगी। डीआईओएस अंशुमान ने बताया कि आयोग की तरफ हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और कृषि विज्ञान विषय के कुल 42 शिक्षक आएंगे।

खून से लथपथ लाश मिली, 9 दिन पहले मुंबई से आई थी, एक हिरासत में

प्रयागराज, (संवाददाता)। सरायइनायत थाना क्षेत्र के जैतपुर हनुमानगंज बाजार में गुरुवार को घर के भीतर 26 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का शव किराए के कमरे में पड़ा मिला। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जौनपुर की रहने वाली उमा (26) का पति दिनेश कुमार मूल रूप से प्रयागराज के उतरांव का रहने वाला है। वह मुंबई में आटो रिक्शा चालक था। करीब पांच साल पूर्व मुंबई में ऊषा से उसकी मुलाकात हुई। दोनों ने लव मैरिज की थी। 11 अगस्त को कोटवां रोड जैतपुर गांव निवासी अनिल स्वर्णकार के घर के दूसरी मंजिल पर किराए का कमरा लेकर दोनों रहने लगे। इनकी चार वर्षीय बेटी स्वीटी है। बताया जाता है कि घटना के समय उषा घर में अकेली थी। दिनेश सुबह ही अपने गांव चला गया था। उसने पत्नी से कहा था कि वह दोपहर बाद तक वापस लौट आएगा। पूर्वान्ह 11:00 के करीब उसकी बेटी की जोर–जोर से रोने की आवाज आई तो पड़ोसी पहुंचे। उन्होंने देखा कि उषा खून से लथपथ मृत पड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। महिला के गले पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं।

दहेज हत्या में वांछित युवक का किया अपहरण

प्रयागराज, (संवाददाता)। पूरामुफ्ती में थाने के पास से 35 साल के एक युवक के अपहरण कर लिया गया है। परिवारवालों का आरोप है कि उसे क्रेटा कार में खींचकर उसमें सवार लोग भाग निकले। उधर पुलिस का कहना है कि युवक दहेज हत्या के मामले में वांछित है। परिवारवालों के आरोपों के बाबत जांच पड़ताल कराई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक महगांव का रहने वाला है और उसका नाम मोनू बताया गया। मोनू के मामा कमलेश कुमार निवासी असरौली ने बताया कि घटना बुधवार दोपहर 11रू45 की है। मोनू किसी काम से जा रहा था तभी पूरामुफ्ती थाने के पास उसे क्रेटा कार से आए कुछ लोगों ने रोक लिया। उन्होंने उससे कुछ देर बातचीत की और फिर उसे कार में खींचकर भाग निकले। इसकी सूचना कुछ स्थानीय लोगों के माध्यम से मिली तो परिवार के लोग मौके पर पहुंचे।

निर्माणाधीन मकान से विद्युत तार चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या।शनिवार को कोतवाली अयोध्या पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से विद्युत तार चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 9 किलोग्राम पीवीसी इंसुलेटेड विद्युत तांबे के तार तथा तार काटने वाला कटर बरामद किया है।इस संबंध मे कोतवाली अयोध्या प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पालेखान पुत्र मो. सैय्यद अली, निवासी मक्खापुर, थाना कोतवाली अयोध्या को पुलिस ने शुक्रवार की रात उदासीन आश्रम से लंगरवीर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीवीसी इंसुलेटेड विद्युत तांबे के तारों का गुच्छा बरामद किया।बरामद तार का वजन करीब 9 किलोग्राम बताया गया है।गिरफ्तारी करने वालों मे उनके अलावा उप निरीक्षक सुनील कुमार गोंड,राहुल बाजपेयी,हेड कांस्टेबल सुनील कुमार,अनुभव सिंह एवं कांस्टेबल राधेश्याम की भूमिका रही।

कोतवाली नगर पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार

अयोध्या। कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी के आभूषण व 20000 रुपये नगद के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक राममूर्ति कनौजिया,शुभम सिंह व आदर्श विक्रम सिंह ने आरोपी निखिल कुमार अग्रहरी पुत्र स्वर्गीय सन्तोष कुमार गुप्ता निवासी ग्राम महरुआ गोला थाना महरुआ जनपद अम्बेडकरनगर वर्ष को शनिवार को देवकाली बाईपास से साकेतपुरी की ओर से सर्विस रोड के समीप गिरफ्तार किया।

अय्यामे अजा का आखिरी दौर आज, सात बाहरी अंजुमनें निकाला गया

अयोध्या। अय्यामे अजा के आखिरी दिन 8 रबीउल अव्वल को राठहवेली में 69वें दौर का मातमी जुलूस निकाला जाएगा। अंजुमन–ए–असगरिया राठहवेली के तत्वावधान में होने वाले आयोजन में अयोध्या के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों और कोलकाता से आने वाली सात अंजुमनें शिरकत करेंगी। जुलूस में अंजुमन–ए–दुआ–ए–सैयदा कोलकाता, अंजुमन– ए–हुसैनिया उन्नाव, अंजुमन–ए–हुसैनिया उस्मापुर जलालपुर, अंजुमन–ए– अजा–ए–हुसैन दोसीपुरा बनारस, अंजुमन–ए–दस्ता–ए–जैनुलआबा रायबरेली, अंजुमन–ए–मोइनुल अजा मोहम्मदी मकबरा कानपुर और अंजुमन–ए–शब्बीरिया सादात जोड़पुर सुल्तानपुर की अंजुमनें शामिल होंगी। कार्यक्रम में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अहमद अली आबदी और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नदीम रजा जैदी मजलिस को खिताब करेंगे। जुलूस छोटी दरगाह से रवाना होकर मस्जिद हसन रजा खां, हसन मंजिल होते हुए राठहवेली पहुंचेगा। यहां मजलिस के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आयोजन को लेकर अंजुमन की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजन में सदर वजीर हैदर, नायब सदर आरिफ हुसैन, सेक्रेटरी सैयद इब्ने हसन शम्सी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान हैदर रूफी और सलमान हैदर पार्षद की प्रमुख भूमिका रहेगी।

बीएसए ने किया राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की एक दिवसीय आंचलिक कार्यशाला का शुभारम्भ

अयोध्या। बच्चे सतत् विकास के लिए विज्ञान और नवाचार मुख्य विषय पर आधारित उप विषयों में किसी एक के अन्तर्गत स्थानीय समस्या का चयन करे।उसके बाद अपनी परियोजना को ग्रुप एक्टिविटी के रूप में विज्ञान विधि से कार्य करते हुए पूरा करे।ये बातें डायट सभागार में आयोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्र व्यापी गतिविधि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की एक दिवसीय आंचलिक कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप मे बीएसए लाल चन्द्र ने कही।कहा कि प्रत्येक विद्यालय से बच्चे अनिवार्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर 31 अगस्त से पहले अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें।कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला समन्वयक एवं कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉ अम्बिकेश त्रिपाठी ने बताया कि आस पास के 10 जिलों अयोध्या, महराजगंज, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, आजमगढ़,सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी सहित मऊ से लभभग 60 शिक्षकों, समन्वयकों ने सहभागिता किया है। डॉ त्रिपाठी ने कहा कि अभी तक अयोध्या जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रगति दूसरे नम्बर पर है जोकि लगभग 500 से अधिक हैं और इसी 31 अगस्त तक 1000 प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन करवा के 2000 बच्चों की सहभागिता कराने का लक्ष्य सुनिश्चित किए जाने के प्रस्ताव किए जा रहे हैं।इस अवसर पर राज्य समन्वयक संस्था वॉलंटरी इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिटी एप्लाइड साइंस (विकास) प्रयागराज के संस्थापक निदेशक डॉ सत्येन्द्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की अवधारणा सहित पिछले 32 वर्षों से इसके सतत् आयोजन करते रहने से बच्चों पर प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। डॉ सिंह ने बहुत सारे छोटी छोटी परियोजनाओं के बारे उदाहरणों सहित प्रकाश डाला।इस मौके पर विजय कुमार, प्रोफेसर डॉ रतन कुमार आनन्द ने समिति एवं आयोजक संस्था विकास प्रयागराज की तरफ से मुख्य अतिथि प्रभारी प्राचार्य डायट के द्वारा अयोध्या के पूर्व समन्वयक डॉ घनश्याम सिंह,जिला अकादमिक समन्वयक डॉ अंजली खरे, पूर्व सह समन्वयक आदित्य सिंह, मार्गदर्शक शिक्षक एवं स्कूल समन्वयक डॉ सुनयना लाल, प्रमुख सन्दर्भ व्यक्ति प्रोफेसर डॉ विजय कुमार एवं प्रोफेसर रतन कुमार आनन्द सहित बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चन्द्र को बाल विज्ञान संचारक सम्मान से सम्मानित किया गया।इस अवसर पर डायट के प्रवक्ता डॉ ओंकार नाथ वर्मा, देवेन्द्र सिंह, मनोज कुमार, महेन्द्र वर्मा, डॉ ऋषि पांडेय, ज्ञानेन्द्र सिंह, डॉ विवेक कुमार सिंह, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉ योगेन्द्र नाथ पाण्डेय, ऋचा उपाध्याय, एस आर जी अमित कुमार मिश्रा सहित सभी विकास खण्डों से बाल विज्ञान कांग्रेस के नोडल समन्वयक रहे।

घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की चयनित छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया उद्घाटन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्राओं के लिए नवनिर्मित बालिका छात्रावास का लोकार्पण रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा किया गया।छात्रावास के निर्माण से सैनिक स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुव्यवस्थित आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।नवनिर्मित छात्रावास भवन का निर्माण चीफ इंजीनियर बरेली जोन, सैन्य अभियंता सेवा (डमै) के अधीन कराया गया है।छात्रावास का उद्देश्य सैनिक स्कूल में चयनित छात्राओं को उनके शैक्षणिक जीवन के दौरान आवश्यक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।लोकार्पण समारोह के दौरान गैरिसन इंजीनियर रानीखेत सुबीर साहा ने रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ को परियोजना की

विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने छात्रावास भवन की प्रमुख विशेषताओं, निर्माण कार्य तथा सैनिक स्कूल की चयनित छात्राओं के लिए इससे होने वाले लाभों से मंत्री को अवगत कराया।इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन मधु सेंगर, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर श्री दीपक कुमार प्रियदर्शी, जिन्होंने परियोजना के कार्य को निष्पादित करवाते हुए इसे पूर्ण कराया, तथा जूनियर इंजीनियर सूबेदार अतुल परमार सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।नवनिर्मित बालिका छात्रावास सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में चयनित छात्राओं के लिए बेहतर आवासीय सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं से छात्राओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण मिलेगा, जिससे वे अपने अध्ययन पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।

भगवान झूलेलाल की शोभायात्रा का केसरवानी समाज ने किया स्वागत

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल का शोभा यात्रा धूमधाम से निकली जिसका भव्य स्वागत केसरवानी समाज के लोगों ने सुभाष नगर होटल कान्हा भूमि भोग के सामने किया जिसमें सिंधी समाज के प्रमुख लोगों को पटका पहनाकर स्वागत किया गया एवं यात्रा में सम्मिलित लोगों को जल पिलाया गया।समाज और सिंधी समाज में पूर्व से ही एक विचार दिखाई पड़ती है जिसका और अटूट एवं मधुर बनाने के लिए ऐसा कार्यक्रम रखा जाता है कार्यक्रम के संयोजक राहुल केसरवानी एडवोकेट बनाए गए हैं द्यकार्यक्रम का संचालन समाज के जिला अध्यक्ष ज्ञान केसरवानी ने किया स्वागत की कड़ी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरली केसरवानी,महामंत्री ललित केसरवानी,संजय केसरवानी अमित केसरवानी,अनुज गुप्ता,राजकुमार गुप्ता(बीएसएनल),ऋषभ केसरवानी, सौरभ केसरवानी,सिद्धार्थ केसरवानी, गणेश केसरवानी,लिटिल केसरवानी,राजू केसरवानी,दुर्गा प्रसाद केसरवानी,महेश केसरवानी,अमित गुप्ता,विशेष केसरवानी और समाज के विभिन्न लोग उपस्थित रहे ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।